



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2001/भाद्र 21, 1923

No. 249]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2001/BHADRA 21, 1923

बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2001

अंतिम निष्कर्ष

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से स्पोर्ट शूज के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

56/1/2000-डी जी एडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसके सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. कार्य पद्धति

1. जांच के निम्नलिखित कार्य पद्धति अपनाई गई है :—

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को नियमों के अधीन विश्वसनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई है कि चीन जनवादी गणराज्य (जिसे एतद् पश्चात् संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्पोर्ट शूज का भारत में पाटन हो रहा है।
- (ii) प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया प्राप्त साक्ष्य के आधार पर नियम 5(4) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध जांच शुरू करने का निर्णय लिया।

प्राधिकारी ने उक्त नियम के उपनियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले उक्त सूचना के प्राप्त होने के बारे में चीन जनवादी गणराज्य को जानकारी दी ।

- iii) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 6402 से 6405 के तहत वर्गीकृत चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए दिनांक 20.11.2000 की सार्वजनिक सूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित कराई ।
- iv) प्राधिकारी ने 25.1.2001 को प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचित किए और ज्ञात हितबद्ध पक्षों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी जिन से अनुरोध किया गया कि वे अपने विचार यदि कोई हों, पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर भिजवाए ।
- v) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को इस अनुरोध के साथ भिजवाई कि वे निर्यातकों तथा हितबद्ध पक्षों को उपरोक्त iv में बताई गई समय सीमा के अंदर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार देने की सलाह दें ।
- vi) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों को 27.4.2001 को अपने विचार मौखिक रूप से देने का अवसर प्रदान किया । विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों को अपने विचार लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । उक्त पार्टियों को विपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त करने और उनका खंडन, यदि कोई हो, भिजवाने की सलाह दी गई ।
- vii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षों के अगोपनीय अंशों वाली फाइल सार्वजनिक फाइल के रूप में सभी हितबद्ध पार्टियों को उनके अनुरोध पर उपलब्ध कराई;

viii) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए जिन तकों ने अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में शामिल किया गया है, उन्हें संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है। तथापि, हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में उठाए गए तकों पर प्रारंभिक निष्कर्षों में तथा/अथवा इन निष्कर्षों में उचित स्थान पर विचार किया गया है।

ix) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधार का खुलासा सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को 30.8.2001 को कर दिया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है।

x) जांच के लिए मानी गई अवधि 1.4.2000 से 30.9.2000(6 माह) है।

ख. घरेलू उद्योग आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा जांच

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों में और प्रकटन विवरण पत्र में भी चर्चा की गई है। जिन विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों में और प्रकटन विवरण पत्र में पहले विचार नहीं किया गया है और जो मुद्दे अब प्रकटन विवरण पत्र के जबाब में उठाए गए हैं, उन पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक वे नियमानुसार संगत हैं और जहां तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं। हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए तकों की जांच की गई है और जहां कही उचित समझा गया है, नीचे संगत पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर निम्नलिखित तक दिए गए हैं-

i) मै. रीबोक इंडिया कंपनी (रीबोक); मै. रीबोक, परफारमैस शूज की बिक्री तथा विपणन संबंधी कार्य में लगी है जिसमें डी एम एक्स, 3 डी, हेक्सालाइट तथा ब्लोन रबड़ जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

ii) मै. एडीडास इंडिया ट्रेडिंग प्रा.लि., अब मैसर्स एडीडास इंडिया मार्किटिंग प्रा.लि. (एडीडास) के नाम से जानी जाती है।

(क) याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक सुनवाई में यह निश्चित रूप से स्वीकार किया है कि उनके पास आवश्यक प्रौद्योगिकी नहीं है और यह कि वे पेटेंटिड प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं और संबद्ध वस्तुओं के लिए भारत के बाहर से आयात पर निर्भर करना पड़ता है।

(ख) घरेलू उत्पादक विशेषीकृत फुटवियर का विनिर्माण नहीं करते हैं अथवा विनिर्माण करने अथवा विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी रखने का दावा नहीं करते हैं।

iii) घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि संबद्ध देश से निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया जा रहा है:

- पी वी सी इन्जैक्टिड शूज, कन्वैस या सिथेटिक अपर्स वाले सैंडिल।
- अपर सोल सहित कैन्वैस शूज।
- रबड़ सिथेटिक या टैक्सटाइल अथवा मिश्रित सामग्री के तथा रबड़ या इवीए सोल वाले स्पोर्ट शूज, खेल कूद के जूते।

प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि जांच की अवधि से पहले वे 3 डी, हैक्सालाईट, डीएमएक्स, ब्लॉन रबड़ इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकियों को इस्तेमाल करके भी बांडिड श्रेणी के शूज का उत्पादन कर रहे थे ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

घरेलू उद्योग द्वारा स्पोर्ट्स शूज की अकेली तथा विशेष श्रेणियों का उत्पादन न किए जाने के बारे में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए तर्कों को नोट करते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे घरेलू उत्पादक अर्थात् मै0 मोजा शूज (प्रा0) लि0 तथा मै0 लखानी इंडिया लि0 हैं, जो बांडिड स्पोर्ट्स शूज की कुछेक श्रेणियों की बिक्री मै0 रीबोक, मै0 नाईक तथा मै0 एडीडास को करते हैं । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान ये दोनों घरेलू उत्पादक मै0 रीबोक तथा मै0 एडीडास द्वारा बताई गई प्रौद्योगिकियों के किसी हायर एंड स्पोर्ट्स शूज (उनके द्वारा विशेष रूप से उत्पादित शूज से इत्तर) का उत्पादन नहीं कर रहे थे । तथापि, दोनों उत्पादकों ने मै0 रीबोक, मै0 नाईक तथा मै0 एडीडास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है । जहां तक विभिन्न ब्रांडों को शामिल किए जाने का संबंध है, विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी सभी ज्ञात ब्रांडों अर्थात् रीबोक, नाईक, एडीडास, कनवर्स, फिला, न्यू बैलेंस, के स्विंस, रकेचर्स प्रोलीन, बाटा, एक्स-एस, डायना पाई, जिआंडा, हारलिंग, लागोंस इत्यादि को ब्रांडिड स्पोर्ट्स शूज की श्रेणी में शामिल करते हैं । तथापि ये ब्रांड केवल संकेतात्मक हैं और असमाप्त हैं । प्राधिकारी दिनांक 25.1.2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों में यथा उल्लिखित जांच के कार्यक्षेत्र तथा घरेलू उद्योग द्वारा इस अनुरोध कि ब्रांडिड शूज का बाजार सीमित है और मै0 रीबोक द्वारा किए गए इस अनुरोध कि ब्रांडिड स्पोर्ट्स शूज का बाजार प्रारंभिक अवस्था में है और यह कि घरेलू उद्योग को अभी हायर एंड शूज प्रौद्योगिकियों प्राप्त करनी है, को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपने निष्कर्ष की पुष्टि करना उचित समझते हैं । विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क शीर्ष 6402 से 6405 के अंतर्गत वर्गीकृत स्पोर्ट्स शूज, गैर-चमड़े के स्पोर्ट्स फुटवियर हैं । इस उत्पाद में केवल पीवीसी इंजेक्टिड शूज रबड़ सोल वाले कैनवस शूज, और रबड़ सिन्थेटिक अथवा कपड़े अथवा दोनों मिश्रित सामग्री

तथा रबड़ अथवा ईवीए सोल के स्पोर्ट्स के शूज शामिल हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पादकों द्वारा भी ब्रांडिड स्पोर्ट्स शूज की कुछेक श्रेणियों का विनिर्माण किया जा रहा है। इस उत्पाद में गैर-ब्रांडिड स्पोर्ट्स शूज (जिन्हे आगे गैर-ब्रांडिड श्रेणी के स्पोर्ट्स शूज भी कहा गया है) तथा ब्रांडिड स्पोर्ट्स शूज जैसे रीबॉक, नाईक, एडीडास, कनवर्स, फिला, न्यू बैलेस के स्थिस, स्केचर्स, पावर प्रोलीन, बांटा एक्स-एस, डायना पाई, जियांग, हारलिंग, लागोस इत्यादि (जिन्ह आगे ब्रांडिड श्रेणी के स्पोर्ट्स शूज भी कि गया हैं) दोनों शामिल हैं।

घ. घरेलू उद्योग का आधार

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति के सबध मे विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं :-

(i) मै० एडीडास

(क) याचिकाकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना परिपूर्ण नहीं है और यह उत्पादन, बिक्री, गैर-चमड़ा निर्यात फुटवियर का निर्यात करने वाले उत्पादकों की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर करना अनुचित और गलत होगा।

(ख) याचिकाकर्ता की इस मामले मे कोई अधिकारिता नहीं है।

(ग) याचिकाकर्ता प्रभावित पार्टियों के हितो का प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि यह मुख्यतः प्रमुख फुटवियर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रमाणित करने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है कि इसका कोई सदर्य स्पोर्ट्स फुटवियर का विनिर्माता है ताकि वह वर्तमान कार्रवाइयो में प्रतिनिधित्व कर सकें।

(घ) संगत आकड़ों के अभाव में, हम इस पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अनुसार आवेदन दायर करने के लिए पात्रता संबंधी मापदण्ड को पूरा करते हैं।

(ड) प्रकटन विवरण के उत्तर में मै0 एडीडास द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि परिषद के सदस्य चप्पल, चमड़ा फुटवियर इत्यादि के विनिर्माण में रत हैं और इसलिए जांच के अंतर्गत उद्योग की सही स्थिति दर्शाना अनुचित होगा।

(ii) मै0 रीबोक

(क) मै0 रीबोक ने यह उल्लेख किया है कि एनसीईआर के सहयोग से उनके द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर देश में स्पोर्ट्स शूज की मांग 150 मिलियन जोड़ा से अधिक है और इसलिए नियमानुसार घरेलू उद्योग के पास कोई आधार नहीं है।

(iii) घरेलू उद्योग

स्पोर्ट्स शूज बाजार के कुल आकार के आधार पर निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों न याचिका का समर्थन किया है जिनका हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक बनता है।

- मै0 एर्पीआई पालिमर्स प्राईवेट लि�0, नई दिल्ली
- मै0 निखिल फुटवियर प्रा0 लि�0, नई दिल्ली
- मै0 फुटवियर (क्लिक) इंडिया प्रा0 लि�0, नई दिल्ली
- मै0 प्रम एटरप्राइजिस, नई दिल्ली
- मै0 वेलकम शूज, नई दिल्ली
- मै0 गैलेक्सी शूज इंडिओ प्रा0 लि�0, नई दिल्ली
- मै0 अदिति इंटरनेशनल, नई दिल्ली

- मै0 लखानी शूज लि�0, फरीदाबाद
- मै0 लिबर्टी ग्रुप, नई दिल्ली
- मै0 मोजा शूज (प्रा0) लि�0

किसी भी घरेलू उत्पादक ने पाटनरोधी जांच का विरोध नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै0 रीबोक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि देश में संबद्ध वस्तु की कुल मांग 150 मिलियन जोड़ा है और पाटनरोधी नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग के पास अपक्षित आधार नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) ने देश में स्पोर्ट्स शूज के लिए नोडल बांडी हान के कारण उनके द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के आधार पर आकलित कुल भाड़ा बांडिड शूज की मांग सहित एक मिलियन जोड़ा बतलाई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै0 सीएलई द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्ध करवाए गए आंकड़े प्राथमिक स्रोत होने के कारण अधिक भरोसेमंद हैं और इसलिए उनका संदर्भ लिया गया है। इसलिए प्राधिकारी बांडिड श्रेणी तथा गैर-बांडिड श्रेणी दोनों सहित स्पोर्ट्स शूट की मांग 140 लाख जोड़ा प्रति वर्ष मानते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने जांच में स्पष्ट रूप से सहयोग किया है, का कुल घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक का हिस्सा बनता है और इसलिए वे पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग के आधार संबंधी मापदण्ड को पूरा करते हैं। अतः प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्ष के पैरा ग(3) में यथा उल्लिखित अपने निष्कर्षों को दोहराते हैं व उनकी पुष्टि करते हैं।

(ड.) समान वस्तु

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समान वस्तुओं के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुराध किए गए हैं :-

(i) मै0 एडिडास

(क) याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित स्पोर्ट्स/कैजुअल शूज विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, कीमत निर्धारण, किंतरण, विपणन एवं वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय हैं। दूसरी और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्नत प्रौद्योगिकी जो कि विदेशी बाड़ों में अन्तर्निहित होती है, भारत में उपलब्ध नहीं है।

(ख) एडिडास शूज का इस्तेमाल करने वाल किसी ग्राहक द्वारा घरेलू स्पोर्ट्स शूज का विकल्प चुनना उसी प्रकार एक दूरवर्ती संभावना है जैसे कि मर्सडीज के मालिक द्वारा मारुति 800 का विकल्प चुनना और यह कि मै0 एडिडास की वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के समान वस्तु नहीं हैं और वे नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

(ग) याचिकाकर्ता ने बताया है कि रथानीय उद्योग द्वारा उत्पादित और आयात किए गए स्पोर्ट्स/कैजुअल शूज का इस्तेमाल भिन्न-भिन्न खण्डों द्वारा किया जाता है। अत अनुरोध है कि वाडेड वस्तुओं को घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के विकल्प के रूप में नहीं समझा जा सकता।

(घ) प्रकटन विवरण के उत्तर में मै0 एडिडास द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि समान वस्तुओं के बारे में उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है। यह अनुरोध किया गया है कि जांच में प्रयुक्त "स्पोर्ट्स शूज" पद एक न्यापक पद है। अनुरोध है कि मै0 एडिडास द्वारा आयातित स्पोर्ट्स शूज सामान्य परियोजनी फुटवियर नहीं है किन्तु इन्हें खास ग्राहकों/खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है और यह कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित शूज बहुप्रयोजनी शूज होते हैं जिनका उल्लेख "सामान्य स्पोर्ट्स वियर" के रूप में किया जा सकता है। भारत में मै0 एडिडास द्वारा बेचे गए स्पोर्ट्स शूज की कीमत 1300/-रुपए से 8000/-रुपए तक के बीच की है जबकि घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित फुटवियर की कीमत सामान्यतः 300/-रुपए से 1200/-रुपए के बीच है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों को नोट करते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां तक ब्रांडेड श्रेणी के तहत डीएम एक्स, २ डी, ब्लोन रबड़, हेक्सालाइट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए विनिर्मित विशेष श्रेणी के स्पोर्ट्स शूज का संबंध है जैसाकि कुछेक आयातका द्वारा उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान इस श्रेणी के शूज का निर्निर्माण नहीं किया है। अतः प्राधिकारी पाटन एवं क्षति के मूल्यांकन हेतु उचित विश्लेषण करते समय डरा घरेलू पर विचार करना उचित समझते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश न ऊपर यथा उल्लिखित विशेष श्रेणी के शूज स इतर आयातित संबद्ध वस्तु नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित वस्तु के समान वस्तु है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि वे विगत में डीएम एक्स, ३ डी ब्लोन रबड़ जैसी प्रौद्योगिकियों से इस प्रकार के हाई एण्ड शूज का उत्पादन कर रहे हैं। तथापि यह नाट किया गया था कि घरेलू उत्पादकों को हायर एण्ड शूज का उत्पादन करने के लिए उत्पादन क्षमता में कुछ बढ़ोत्तरी करने की जरूरत है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा ग(2) में दिए गए अपने निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

(च) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

(i) मै0 प्रोलीन स्पोर्ट्स सिस्टम

(क) शूज का आयात उन कीमतों पर किया जाता है जो कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अमरीकी डालर के रूप में तय की जाती हैं।

(ख) चीनी उत्पादकों के पास ऐसी सुविधाएँ हैं जिनमें बड़े पैमाने पर किफायते होती हैं और विभिन्न दशा का समान कीमतों पर वितरण किया जाता है।

(ii) मै0 रीबोक

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बांड रहित तथा लो एण्ड ब्रांडेड एवं ब्रांडेड फूटविशर के बीच किए गए भेद में पूर्णतः पक्षपात की वू आती है। इसे अनेक बांड है जिनका भारत में आयात किया न रहा है और जिन्हें बांड रहित तथा लो एण्ड ब्रांडेड श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। नन्म एमएनसी बांड जैसे कि कनवर्स एफआईएलए न्यू वैलेंस, के स्विस, रकैचर्स इत्यादि शामिल हैं। इससे इन बांडों के शूज को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है जो समान खुदरा मूल्य पर उपलब्ध है।

(ख) मै0 रीबोक ने लांच अवधि के दौरान उनके द्वारा चीन से किए गए आयातों के ब्यौरे भी उपलब्ध किए हैं।

(ग) भारत को निर्यातित इसी प्रकार के माडलों की चीन में खुदरा कीमतें कमीवंश समान हैं। इसलिए पाटन का प्रश्न नहीं उठता।

(iii) मै0 एडिडास

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ निश्चित स्रोत की सूचना पर विश्वास किया है किन्तु मै0 एडिडास को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है और इसलिए हम कोई प्रभावी अनुरोध नहीं कर सकते।

(ख) मै0 एडिडास ने जांच अवधि के दौरान किए गए आयातों के ब्यौरे और भुगतान, छूट और कमीशन की प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे सहित आयातक प्रश्नावली में सूचना प्रस्तुत की है।

उपरोक्त अनुरोधों को नोट करते हुए प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा-ग (4) में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में अपने निष्कर्षों का स्मरण करते हैं और उन्होंने प्रारंभिक निष्कर्षों में यथानिर्दिष्ट सामान्य मूल्य के परिकलन के बारे में इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया है।

सामान्य मूल्य का निम्नानुसार आकलन किया गया है।

सामान्य मूल्य

चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। तथापि प्राधिकारी को कुछेक भरोसेमंद श्रोतों द्वारा घरेलू बिक्री कीमतों और तीसरे देशों की कीमतों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत उपलब्ध कराई गई है जिसका सत्यापन भी किया गया है। संबद्ध देश के नियातकों की ओर से असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन करना उचित समझते हैं सामान्य मूल्य का परिकलन ब्रांड रहित और ब्रांड युक्त श्रेणी के स्पोटर्सशूज के लिए अलग-अलग दिया गया है। इसे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमतों और विश्वसनीय श्रोतों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर भारत से भिन्न तीसरे देशों का उसकी निर्यात कीमत के साथ सह-संबद्ध भी किया गया है। संबद्ध देश में ब्रांड रहित स्पोटर्सशूज और ब्रांडयुक्त स्पोटर्सशूज का परिकलित भारित औसत सामान्य मूल्य क्रमशः ... रूपए प्रति जोड़ा और ... रूपए प्रति जोड़ा बैठता है। भारित औसत सामान्य मूल्य में सभी श्रेणियों और साइजों के स्पाटर्सशूज शामिल हैं। इस पद्धति में कुछेक हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए इस आशय के मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा कि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित शूज की श्रेणी के लिए उचित तुलना की जाए।

निर्यात कीमत

जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वर्तु (गैर-ब्रांडेड श्रेणी) की आयात कीमत सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी है और यह डी जी सी आई एस आंकड़ों से भी उपलब्ध है। स्पोटर्स शूज की ब्रांडेड श्रेणी की आयात कीमत कुछेक आयातकों जैसे मै0 रीबोक, मै0 एडिडास और मै0 बाटा द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन स्पोटर्स शूज की गैर-ब्रांडेड और ब्रांडेड श्रेणी के लिए अलग-अलग निम्नानुसार किया गया है:-

महानिदेशालय ने घरेलू उद्योग, सीमाशुल्क प्राधिकारियों और कुछेक आयातकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर और उसे डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के साथ सह-सम्बद्ध करने के पश्चात घरेलू उद्योग और आयातकों से उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना तथा ऐसे मामलों में अपनायी गयी संगत प्रक्रिया के आधार पर xxx,xxx,xxx,xxx और xxx रुपए/जोड़े की सीमा तक समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय स्वदेशी भाड़े इत्यादि के लिए समायोजन की अनुमति देकर स्पोटर्स शूज की गैर ब्रांडेड श्रेणी की कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन किया है।

जहाँ तक मै0 मोजा शूज (प्रा0) लि0. और मै0 लखानी इंडिया लि. द्वारा विनिर्मित जूता की ब्रांडेड श्रेणी का संबंध है, प्राधिकारी ने आयातों के संबंध में मैसर्स बाटा और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पर विचार किया है क्योंकि यह स्पोटर्स शूज की वह रेज श्रेणी है जो घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित ब्रांडेड स्पोटर्स शूज के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। पूर्वोक्त पैरा में यथा-सल्लिखित समायोजनों की अनुमति भी दी गयी है। गैर-ब्रांडेड स्पोटर्स शूज और ब्रांडेड शूज की भारित औंसत कारखाना गत निर्यात कीमत क्रमशः xxxx रुपए/जोड़ा और xxx रुपए/जोड़ा वर्ती है।

(छ) पाटन-सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करगा। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वारा स्तर पर की जाएगी और यथा संभव उसी समयावधि के दौरान की गयी बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छृट दी जाएगी, अंतर में शामिल है - स्थितियों में एवं बिक्री की शर्तों में अंतर, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, वार्तविक विशेषताएं तथा कोई अन्य अंतर जो कीमत तुलनीय को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।"

सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के उद्देश्य स प्राधिकारी ने, जैसा कि उपर बताया गया है, कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार किया है।

निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है -

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (रूपए/जोड़ा)	निर्यात कीमत (रूपए/जोड़ा)	पाटन मार्जिन (%)
सभी निर्यातक/उत्पादक			
(क) गैर-ब्रांडेड श्रेणी के र्पोटर्स शूज	xxxx	xxx	104.6
(ख) ब्रांडेड श्रेणी के र्पोटर्स शूज	xxxx	xxx	92.6

दोनों श्रेणियों अर्थात् गैर-ब्रांडेड और ब्रांडेड के लिए निर्यातकों के लिए उपरोक्तानुसार पाटन मार्जिन क्रमशः 104.6% और 92.6% बनता है।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनेक हितबद्ध पार्टियों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

(i) काउसिल फॉर लैंडर एक्सपोर्टर्स
(क) ब्रांडेड श्रेणी के जूतों में नाइक, रीबोक, एडीडास और अन्य ब्रांड जैसे योनेक्स, कन्वर्स, न्यू वेलेस इत्यादि का भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इनसे भी चीन जनवादी गणराज्य से वर्स्तु क पाटन के कारण भारतीय उद्योग को समान क्षति हुई है।
(ख) ब्रांडेड श्रेणी के जूतों के लिए डालर/प्रति जोड़ी में आयातों के अधिकतम पहुँच मूल्य का 18.44 अमरीकी डालर के वर्तमान स्तर के मुकाबले बढ़ाकर 25 अमरीकी डालर किया जाना चाहिए जिसमें फुटवियर के बीच प्रमुख क्षेत्र शामिल नहीं हैं जिनका ब्रांडेड श्रेणी के तहत आयात किया जा रहा है और जो घरंतू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है।

(ii) मै0 मोजा शूज (प्रा.) लि0

(क) कंपनी का क्षमता के बहुत कम उपयोग के कारण हानि हुई है और यह कि ब्रांडेड उत्पाद के आयात के कारण वृद्धि सम्भव नहीं थी। आयातित वर्स्तु बहुत कम कीमत पर आ रही है और इसलिए मुश्किल से ही कोई मार्जिन प्राप्त नियमित किया जा सकता है। मै0 मोजा शूज (प्रा.) लि. नियमित रूप से यू.एस.ए को ब्रांडेड उत्पादों का निर्यात करता रहा है, जो इसकी विशेषज्ञता का प्रमाण है।
(ख) घटिया क्वालिटी और चीन से र्पोटर्स शूज/केजूअल शूज के कम कीमत पर आयातों के कारण हमारे उत्पादन और विपणन को भारी क्षति हुई है।

(iii) मै. ब्रोलीन स्पोर्ट्सिस्टम

(क) आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास न तो प्रौद्योगिकी है और न ही वे चीन से आयात किए जा रहे जूतों की रेंज का विनिर्माण कर रहे हैं:

(iv) मै. बाटा इंडिया लि.

(i) यदि घरेलू उद्योग को आयातों की बढ़ से बचाने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो संगठित क्षेत्र सहित समूचा फुटवियर उद्योग भारी घाटे में आ जाएगा।

(v) मै. रीबोक इंडिया कंपनी

(क) मै. रीबोक भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जरूरतें को पूरा करते हैं जिससे भारतीय स्पोर्ट शूज उद्योग के विकास में कोई भी बाधा नहीं आती है। भारत में मै. रीबोक द्वारा उतारे गए अपने उत्पाद का सबसे अधिक लाभानुभोगी घरेलू उद्योग रहा है जो उर्ध्वगामी समग्र मूल्य शृंखला से लाभान्वित हुआ है और भारत में फुटवियर बाजार का विस्तार हुआ है।

(ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित पहुंच मूल्य की परिभाषा अपूर्ण है और इसके सी डी और एस ए डी को शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) मै. रीबोक द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से आयातित शूज से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंची है क्योंकि ये उन उत्पादों के समान नहीं हैं जिनका निर्माण भारत के घरेलू उत्पादकों द्वारा किया जाता है।

(घ) मै. रीबोक परफारमेंस शूज की बिक्री और विपणन के कार्य में लगा हुआ है जिसमें डी एम एक्स, 3 डी, हैक्सालाइट और ब्लॉन रबड़ जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल होती हैं जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत में ब्रांडेड जूता बाजार ही केवल उभरता हुआ बाजार है और यदि प्रतिस्पर्धा के अवसर उचित हैं और चीनी ब्रांडेड जूतों को भारत में पाटन की अनुमति नहीं दी जाती है तो घरेलू उत्पादक उभर सकते हैं और वे शीघ्र ही बाहरी निर्यातकों और साथ ही साथ भविष्य में निर्यात से प्रतिस्पर्धा करने में रक्षम हो जाएंगे ।

(घ) वे कीमतें मैं 0 रीबोक आयात कर रहा है उस स्तर से काफी अधिक हैं जिस पर भारतीय उद्योग प्रचालन कर रहा है । ऐसे कोई भारतीय स्पोर्ट्स शूज नहीं हैं जो ऐसी उच्ची कीमत पर बेचे जा रहे हों जिस पर मैं 0 रीबोक आयात कर रहा है ।

(ङ) कीमतों और गुणवत्तायुक्त जूतों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों की प्राधिकारी द्वारा आगे समीक्षा करन की आवश्यकता है ताकि प्रचलित स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके ।

(च) स्पोर्ट्स फुटवियर का कुल बाजार आकार 150 मिलियन जोड़े का है जिसमें .05 प्रतिशत का आयात बनता है जिससे स्पोर्ट्स फुट वियर के घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति नहीं होती है ।

(vi) मैं 0 एडीडास इंडिया ट्रेडिंग प्राति लिंग

(क) घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण दिया गया है जो कि प्रतिस्पर्धा के समान अवसर और बड़े पैमाने पर किफायतों के मानदंडों के खिलाफ है ।

(ख) याचिकाकर्ता ने सभी प्रकार के स्पोर्ट्स/जूतों के संबंध में सूचना दी है और इस बारे में कोई अलग सूचना नहीं है । इससे सही तर्चीर प्रदर्शित नहीं होती है ।

(ग) याचिकाकर्ता ने कहा है कि चीन के मूल की संबद्ध वस्तु हांगकांग, नेपाल तथा सिंगापुर के रास्ते से आ रही है और इसलिए चीन से होने वाला निर्यात बहुत अधिक है । याचिकाकर्ता का निवेदन सही नहीं है क्योंकि वस्तुओं का आयात करते समय आयातक मूलता के देश तथा निर्यात पत्तन का उल्लेख करने की सांविधिक आवश्यकता होती है ।

(घ) प्रकटन विवरण के उत्तर में यह निवेदन किया गया है कि मै0 एडीडास द्वारा स्पोर्ट्स शूज का आयात करने की वजह से घरेलू बाजार को कोई वार्तविक क्षति नहीं हुई है ।

(ङ.) प्रकटन विवरण के उत्तर में मै0 एडीडास द्वारा यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग की यह दलील की चीन के मूल के जूते अन्य देशों के जरिए आ रहे हैं, गलत है क्योंकि आयातक को आगम बिल पर उद्गम वाले देश की घोषणा करना अपेक्षित होता है । घरेलू विनिर्माताओं की लाभप्रदता, बाजार हिस्से और क्षमता उपयोग में चीन के मूल के स्पोर्ट्स शूज के पाठन की वजह से कमी नहीं आयी है बल्कि अन्य आर्थिक कारकों जैसे अकुशलता, संचालन के कमजोर स्तर, सस्ती कच्ची सामग्री का उपयोग, श्रमिक संबंधी समस्याएं इत्यादि की वजह से कमी आयी है । घरेलू उद्योग नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ विश्व स्तर का संयंत्र स्थापित कर सकता था और सरकारी मजदूरी की सहायता से बड़ी मात्रा में निर्यात कर सकता था ।

(vii) मैसर्स इंडियन स्पोर्ट्स वियर मार्किटिंगर्स एशोसिएशन

(क) एन सी ए ई आर द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आयातों का प्रतिशत कुल बाजार की तुलना में नगण्य है ।

(ख) उत्पादक घरेलू विनिर्माताओं से उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग करके फुटवियर प्राप्त कर रहे हैं और इससे घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है ।

(ग) गत दो वर्षों में घरेलू स्पोर्ट्स शूज की औसत कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है और इस कीमत की बढ़ती हुई प्रवृत्ति जांच अवधि के दौरान देखी गयी है ।

(घ) निर्यातक/उत्पादक और घरेलू विनिर्माता अलंग अलंग बाजार खड़ा म प्रचालन करते हैं और यह कि आयातों की वजह से घरेलू उत्पादकों का कोई क्षति नहीं हुई है।

प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए निवेदनों को देखते हुए यह नोट करते हैं कि उपर नियम ॥ अनुबध -॥ के अतर्गत जब क्षति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में घरेलू उद्योग का होने वाली क्षति का निर्धारण भी शामिल होगा ॥ ऐसा करते समय सभी संगत तथ्या का ध्यान में रखा जाएगा जिनमें शामिल हैं पारित किए गए आयातों की मात्रा घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव ॥ । पारित आयात का कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार करते समय यह जाच करना आवश्यक समझा गया है कि आयातों के पाटन से कीमत में भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कोई उल्लेखनीय गिरावट आयी है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक घटाने या कीमत को बढ़ाने से राक्ने से मदद मिली है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ सकती थी ।

उक्त नियमावली के अनुबध-॥ (iv) के अनुसार भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जाच करने के लिए हम ऐसे संकेतकों पर विचार कर सकते हैं जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग बिक्री की मात्रा, भड़ार, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय पाटन की मात्रा तथा मार्जिन क्षेत्र इत्यादि ।

प्राधिकारी ने निम्नानुसार पाया है:-

- (1) डी जी सी आई एस के अनुसार चीन अन्यादी गणराज्य से संबद्ध वरतु के आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है जो 1999-2000 में 4.68 लाख जोड़े से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिक) में 5.9 लाख जोड़े हो गए हैं।
- (2) घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वरतु का उत्पादन 1999-2000 में 80.88 लाख जोड़े से घटकर जांच अवधि (वार्षिक) में 76.55 लाख जोड़े रह गया।
- (3) घरेलू उद्योग का संबद्ध वरतु के संबंध में क्षमता उपयोग 1999-2000 में 76.34 प्रतिशत से घटकर जांच अवधि में 72.25 प्रतिशत रह गया।
- (4) उद्योग की लाभप्रदता 1999-2000 में *** रूपए से घटकर जांच अवधि में *** रूपए रह गयी।
- (5) प्रति जाड़ा भारित औसत लाभ 1999-2000 में *** रूपए प्रति जाड़ा से घटकर जांच अवधि में *** रूपए प्रति जाड़ा रह गया। जांच अवधि में निवल बिक्री प्राप्ति भी क्षति रहित कीमत (एम आई पी) से कम रही है।
- (6) मैसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड के ग्राहंड श्रेणी के स्पोर्ट्स शूज की विक्री प्राप्ति 1999-2000 में ** रूपए प्रति जोड़े से घटकर जांच अवधि में ** रूपए प्रति जाड़ा रह गयी है। मैसर्स मांजा शूज (प्रा०) लि० और मैसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड का क्षमता उपयोग ईष्टतम ये कम रहा है और जांच अवधि के दौरान तुलनीय श्रेणी के स्पोर्ट्स शूज के पाटित आयातों की वजह से कीमत में कमी आयी है। जहाँ तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का सबध है कि बाड़िड जूता की श्रेणी के संबंध में इनकी वृद्धि दर में कमी रही है, प्राधिकारी

नोट करत है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि ब्राडिड श्रेणी के स्पोटर्स शूज की उच्चतम रेंज की मांग अधिक नहीं रही है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में ब्राडिड श्रेणी के स्पाटर्स शूज में हुई क्षति का मैरसर्स माजा शूज (प्रा०) लि० और मैरसर्स लखानी इंडिया लि० द्वारा विनिर्मित किए जा रहे तथा दबं जा रहे जूतों की श्रेणी तक वहतर तरीके से सीमित किया जाता है और हायर एण्ड स्पाटर्स शूज की कम मांग जूतों को हायर एण्ड श्रेणी की वृद्धि का सीमित करने वाला कारक है। उपरोक्त आर्थिक संकेत समग्र एवं सचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग का पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। यह प्रमाणित करने में कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है, प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देश से संबद्ध वर्स्टु के पाटित आयातों से घरेलू बाजार में संबद्ध वर्स्टु की कीमतों में कमी आई है और इसलिए, घरेलू उद्योग को अलाभकारी कीमतों पर विक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभ प्रदत्ता में कमी आई और वित्तीय हानि हुई। चूंकि संबद्ध वर्स्टु की समूची मांग में संचयी रूप से गिरावट नहीं आई है, इसलिए यह उद्योग का हुई क्षति में एक सहायक कारक नहीं है।

(ङ) क्षति संबंधी निष्कर्ष

प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि

(i) संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित सभी स्वरूपों यानि श्रेणी, आकार, बांड़ड/गैर-गांड़ड में संबद्ध वर्स्टु का भारत को निर्यात उसक सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है।

(ख) घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे के रूप में वारस्तविक क्षति हुई है जिसका कारण पाटित सबद्ध वस्तु की कम पहुँच कीमत की वजह से कीमत में आयी गिरावट के कारण निवल बिक्री प्राप्ति में कमी आना है।

(ग) घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित सबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुयी है।

(घ) घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक रक्केतक जैसे उत्पादन, औसत बिक्री प्राप्ति और वित्तीय हानि, समग्र एवं संचयी रूप से यह प्रमाणित करते हैं कि घरेलू उद्योग को वारस्तविक क्षति हुयी है।

अतः यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को वारस्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुया है। यह प्रमाणित करते समय कि घरेलू उद्योग का वारस्तविक क्षति संबद्ध दश से हुए आयातों के कारण हुई है। प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देश से किए गए पाटित नियांतों से घरेलू वाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों में कमी आयी है और घरेलू उद्योग को अलाभाकारी कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य हाना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है। घरेलू उद्योग का उत्पादन में कमी, क्षमता उपयोग में गिरावट और बिक्री प्राप्ति में क्षति रहित कीमत में अधिक गिरावट आने की वजह से क्षति हुई है।

6) भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने निवेदन किया है कि पाटनरांधी शुल्कों का स्वरूप सामान्यतया सरक्षणवादी हाता है। प्राधिकारी का मानना है कि मैसर्स रीबोक ने यह इंगित किया है कि उन्हान

भारत में ब्रांडेड स्पोट्स शूज के बाजार का सर्वद्वन्द्व करने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एवं अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में सहायता की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ-साथ कुछेक घरेलू उत्पादकों जैसे मैसर्स मोजा शूज (प्रा०) और मैसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड ने मैसर्स रीबोक, मैसर्स एडीडास और मैसर्स नाइक इत्यादि की ऐसी श्रेणी के ब्रांडेड जूतों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। यदि पाटन संघरेलू उत्पादकों के कार्य निष्पादन एवं स्वारक्ष्य पर प्रभाव पड़ता है तो इससे उपभोक्ताओं के लिए भी संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर अंतरोगत्वा प्रभाव पड़ेगा। यह भी सच है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से अंतिम उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु का कीमत स्तर कतिपय सीमा तक प्रभावित हो सकता है। तथापि, ऐसे पाटनरोधी शुल्कों की लेवी से पाटन के व्यवहारों द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ सीमित हो जाएंगे और इनसे घरेलू उद्योग का आगे हास रुकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों को लगाने से संबद्ध देश से आयात भी किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ट. पहुँच मूल्य

पहुँच मूल्य का निर्धारण सीमाशुल्क के लागू स्तर (धारा 3, 3क, 8ख. 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर) तथा एक प्रतिशत उत्तराई प्रभार जोड़ने के बाद किया गया है।

ठ. निष्कर्ष

पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद यह पाया गया है कि:-

(क) संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पूर्वोक्त पैरा जा (।) में यथा इंगित रूपों में तथा श्रेणी में संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है।

(ख) घरेलू उद्योग को उत्पादन में कमी के कारण वास्तविक क्षति हुई है और इसे पार्टित संबद्ध वस्तुओं की कम पहुँच कीमत के चलते कीमत अवमूल्यन के कारण बिक्री कीमत में कमी की वजह से वित्तीय क्षति हुई है।

(ग) घरेलू उद्योग को यह क्षति संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाठन के कारण हुई है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु, जा अध्याय-64 के तहत आती है, के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

(घ) यह विचार किया गया था कि पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जाए ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाए। तदनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि संबद्ध देश, अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्पोर्ट शूज, जो सीमाशुल्क टैरिफ. के अध्याय 64 (सीमाशुल्क शीर्ष सं 6402 से 6405) के तहत आते हैं, के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। संबद्ध वस्तुएं केवल पीवीसी इंजेक्टेड जूते, रबड़ सोल वाले कैनवास और रबड़ अथवा ईवीए सोल वाले रबड़ सिंथेटिक अथवा टैक्सटाईल अथवा मिश्रित सामग्री से बने स्पोर्ट शूज हैं जैसाकि पूर्वोक्त पैरा ग(।)

म भी दर्शाया गया है। पाटनरोधी शुल्क नीचे कालम-3 में उल्लिखित राशि तथा अमरीकी डालर/जोड़े में आयातों की पहुँच कीमत के बीच का अतर होगा।

क्र सं	निर्यातक/उत्पादक का नाम	राशि (अमरीकी डालर/जोड़ा)
	चीन जन0गण0 के सभी निर्यातक/उत्पादक (क) ब्रांडेड श्रेणी के स्पोर्टशूज को छोड़कर केवल गैर- ब्रांडेड श्रेणी के स्पोर्टशूज	5.044
	(ख) ब्रांडेड श्रेणी के स्पोर्ट शूज (अर्थात्, रीबॉक, नाईक, अदिदास, कनवर्स, फिला, न्यू बैलेंस, के स्विस, स्केचर्स, प्रोलीन, बाटा एक्स-एस, डायना पाई, जियांग, हारलिंग, लागोस इत्यादि)	12.9

इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा।

उपरोक्त के अधीन रहते हुए, प्राधिकारी 25.1.2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियन्त्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी।

एल. थी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th September, 2001

FINAL FINDINGS**Subject :** Anti-Dumping investigation concerning imports of sports shoes from P.R.C.

56/1/2000-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A PROCEDURE

The procedure described below has been followed:

- i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received information from reliable sources regarding dumping of sports shoes (hereinafter also referred to as subject goods) into India originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as subject country).

- ii) The Authority on the basis of *prima-facie* evidence as received decided to initiate the investigation against imports of subject goods from People's Republic of China under Rule 5 (4). The Authority notified the Embassy of People's Republic of China in New Delhi about the receipt of the information before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules.
- iii) The Authority issued a public notice dated 20.11.2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under custom Head 6402 to 6405 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from People's Republic of China.
- iv) The Authority notified preliminary findings dated 25.01.2001 forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;
- v) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the subject country in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (iv) above.
- vi) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 27.04.2001. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

- vii) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;
- viii) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in the preliminary findings and/or these findings;
- ix) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 30.8.2001 and comments received on the same have also been duly considered in these findings.
- x) The period of investigation (POI) considered is 1.4.2000 to 30.09.2000 (6 months).

B. VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY

The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The Authority notes that the following arguments have been made on the product under consideration:-

(i) M/s Reebok India company (Reebok)

M/s Reebok is engaged in selling and marketing of performance shoes, which involves technologies like DMX, 3D, Hexalite and Blown Rubber, which are not available in India.

(ii) M/s Adidas India Trading Pvt. Ltd. now known as M/s Adidas India Marketing Pvt Ltd. (Adidas)

- a) The petitioners have categorically admitted in the public hearing that they do not possess the requisite technology and that they are using patented technology and have to resort to importing the subject goods from outside India.
- b) The domestic producers do not manufacture or claim to manufacture or possess the requisite technology for manufacture of specialized footwear.

(iii) Domestic Industry

The domestic industry has informed that the following goods are being imported from the subject country:

- PVC injected shoes, sandals with canvas or synthetic uppers.
- Canvas shoes with upper soles
- Sports shoes with rubber synthetic or textiles or combination materials and with rubber or EVA sole.

In response to the Disclosure, the domestic industry has informed that prior to POI they were producing branded category sports shoes using technologies like 3D, hexalite, DMX, blown rubber etc. also

EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority noting the arguments raised by various interested parties on the exclusive and special categories of sports shoes not being made by the domestic industry notes that there are domestic producers viz. M/s Moza Shoes (P) Limited and M/s Lakhani India Limited who sell certain categories of branded sports shoes to M/s Reebok, M/s NIKE and M/s Adidas. The Authority notes that during the POI these two domestic producers were not producing any higher end sports shoes (other than those which were specifically produced by them) of the technologies as indicated by M/s Reebok and M/s Adidas. However, the two producers have set up production facilities to cater to the requirements of M/s Reebok, M/s NIKE and M/s Adidas. As regards inclusion of various brands the Authority noting the submissions made by various interested parties includes all known brands viz. Reebok, Nike, Adidas, Converse, Fila, New Balance, K swiss, Sketchers, Proline, Bata, X-ess, Diana Pi, X-iang, Harling, Lagos etc in the category of branded sports shoes. These brands are however only indicative and not exhaustive. The Authority keeping in view the scope of investigation as indicated in the preliminary finding dated 25.1.2001 and also the submissions by the domestic industry that the branded shoes market is limited and also by M/s Reebok that the branded sports shoe market is in infancy stage and that the domestic industry is yet to acquire higher end shoe technologies, considers it appropriate to confirm its finding on the product under consideration as indicated in para C(1) of the preliminary finding.

The product under consideration is sports shoes, non-leather sports footwear classified under the Custom Head 6402 to 6405. The product covers PVC injected shoes, Canvas shoes with rubber soles and Sports shoes with rubber synthetic or textiles or combination materials and with rubber or EVA sole only. The product covers both non-branded sports shoes (hereinafter also called non-branded category sports shoes) and branded sports shoes like Reebok, Nike, Adidas, Converse, Fila, New Balance, K. Swiss, Sketchers, Power, Proline, Bata X-ess, Diana Pi, X-iang, Harling, Lagos etc. (hereinafter also called branded category sports shoes), keeping in view the fact that certain categories of branded sports shoes are being manufactured by the domestic producers also.

D. STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY

The Authority notes that the following submissions have been made by various interested parties on standing of the domestic industry:-

(i) M/s Adidas

a) The petitioner has himself admitted that information provided by them is in-exhaustive and does not give true picture of production, sales, producers of non-leather exports footwear. Therefore, it would be inappropriate and improper to rely on the information furnished by the petitioner.

b) The petitioner does not have locus standi in the matter.

c) The petitioner does not represent the interests of the affected parties since it primarily represents the major footwear industry and no information has been provided to establish that any of its members are manufacturers of sports footwear so as to make representation in the present proceedings.

d) In the absence of relevant data, we are unable to comment whether the domestic producers satisfy the eligibility criteria for filing the application as per Rule 2(b).

e) In response to the Disclosure Statement, it has been submitted by M/s Adidas that members of the Council are engaged in manufacturing of chappals, leather footwear etc. and, therefore, it would be inappropriate to reflect the true picture of the industry under investigation.

(ii) M/s Reebok

a) M/s Reebok has indicated that the demand of the sports shoes in the country is above 150 million pairs on the basis of NCAER assisted survey carried out by them and therefore the domestic industry has no standing as per rules.

(iii) Domestic Industry

Based on the total size of the sports shoes market, the following domestic producers who have supported the petition constitute more than 50% of the total domestic production.

- M/s API Polymers Private Limited, New Delhi
- M/s Nikhil Footwear Private Limited, New Delhi
- M/s Footwear (Klick) India Private Limited, New Delhi
- M/s Prem Enterprises, New Delhi
- M/s Welcome Shoes, New Delhi
- M/s Galaxy Shoes (I) Private Limited, New Delhi
- M/s Aditi International, New Delhi
- M/s Lakhani Shoes Limited, Faridabad
- M/s Liberty Group, New Delhi
- M/s Moza Shoes (P) Limited

None of the domestic producers have opposed the anti-dumping investigation

EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes that it has been submitted by M/s Reebok that the total demand of the subject goods in the country is 150 million pairs and that the domestic producers do not have the requisite standing as per Anti-Dumping Rules. The Authority in this regard also notes that M/s Council for Leather Exports (CLE) representing the domestic industry has provided the total demand as worked out on the basis of the survey conducted by them being the nodal body for sports shoes in the country including the demand of the branded shoes as one million pairs. The Authority notes that the data as provided by M/s CLE on the basis of survey conducted by them is more reliable being from the primary sources and therefore has been referenced. The Authority therefore considers the total demand of sports shoes including both branded category and non-branded category as 140 lakh pairs per annum. The Authority notes that the domestic producers who have extended explicit support to the investigation account for more than 50% of the total domestic production and therefore, satisfies the criteria of standing of the domestic industry as per Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. The Authority, therefore, recalls and confirms its finding as given in para C(3) of the preliminary finding.

E. LIKE ARTICLE

The Authority notes that the following submissions have been made by various interested parties on like articles:-

(i) M/s Adidas

- a) The petitioner have alleged that the sports/casual shoes produced by the Indian industry and those imported from China are comparable in terms of characteristics, manufacturing process, technology, functions and uses, pricing, distribution, marketing and tariff classification of the goods. On the other hand, in the public hearing they have indicated that the advanced technology, which is inherent in foreign brands, is not available to India.
- b) The likelihood of a customer using Adidas shoes opting for domestic sports shoes is a remote possibility like a Mercedes owner opting for Maruti 800 and that the goods of M/s Adidas and those manufactured by domestic industry are not Like Article and are not interchangeable within the meaning of the Rule 2(d).
- c) The petitioner has stated that the sports/casual shoes produced by local industry and those imported are used by different segments. Therefore, it is submitted that the branded goods cannot be treated as substitute for the goods manufactured by the domestic industry.
- d) In response to the Disclosure Statement, it has been submitted by M/s Adidas that their earlier submissions on like articles have not been considered. It has been submitted that the "sports shoes" term given in the investigation is a generic term. It is submitted that the sports shoes imported by M/s Adidas are not general purpose footwear but are designed to cater to the needs of particular consumers/sports person and that the shoes manufactured by domestic manufacturers are multipurpose shoes which may be termed as "general sportswear". The price band of sports shoes sold by M/s Adidas in India ranges between Rs.1300 to Rs.8000 whereas the price band of footwear manufactured by the domestic producers generally ranges between Rs.300 to Rs.1200.

EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes the arguments made by various interested parties. The Authority notes that as regards the special category sports shoes under branded category manufactured using DMX, 3D, blown rubber, hexalite, technology, as indicated by certain importers, the domestic industry has not manufactured such category of shoes in the POI. The Authority therefore considers it appropriate to look into this aspect while making appropriate analysis for evaluation of dumping and injury. The Authority notes that the subject goods imported other than the special category shoes as indicated above from the subject country are like articles to the goods manufactured by the domestic producers within the meaning of the Rules 2(d). The Authority notes that the domestic industry in response to the disclosure has indicated that they had been producing such high-end shoes with technologies like DMX, 3D, blown rubber in the past. However, it was also noted that the domestic producers would need some additionality in production facility to produce higher end shoes. The Authority keeping in view the above confirms its finding in para C(2) of the preliminary finding.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

The Authority notes that none of the exporters/producers from PR China have responded. The Authority notes that various interested parties have made the following submissions.

(i) M/s Proline Sportsystem

- (a) The imports of shoes are made at prices which are internationally fixed in US\$ terms.
- (b) Chinese have facilities, which have economies of scale and the distribution across various countries at same prices.

(ii) M/s Reebok

- a) The distinction made by DA between un-branded and low end branded and branded footwear smells absolutely of partisan attitude. There are a plethora of brands which are being imported in India which have been classified under the non-branded and low end branded category which include MNC brands like Converse, FILA, New Balance, K-Swiss, Sketchers etc. This has given an un-fair advantage to these branded footwear which are available at the similar retail prices.
- b) M/s Reebok has also provided the details of the imports made by them during the POI from China.

c) The retail prices in China of similar models exported to India are more or less at par. Therefore, the question of dumping does not arise.

(iii) M/s Adidas

a) The Designated Authority for the purpose of normal value has relied on information of certain source but not made available any information to M/s Adidas, and, therefore, we cannot make an effective submission.

b) M/s Adidas have provided the information in the importers questionnaire with details made during POI and details on procedure for payment, discounts and commission.

The Authority noting the above submissions recalls its finding on normal value and export price in para C(4) of preliminary finding and has adopted the same methodology regarding constructing normal value as indicated in the preliminary finding.

The normal value is evaluated as under:-

Normal Value

None of the exporters/producers in PR China have responded to the Questionnaire sent by the Authority. The information on domestic selling prices and prices to the third countries have, however, been provided by certain reliable sources to the authority. The authority also notes that the cost of production of the subject goods in India has been made available by the domestic industry, which has also been verified. In view of no cooperation from the exporters from the subject country, the Authority considers it appropriate to construct the normal value as per the best available information in accordance with the Anti-Dumping Rules. The normal value has been constructed separately for non-branded and branded category of sports shoes. This has also been co-related with the Domestic selling prices of the subject goods in subject country and also its export prices to the third countries other than India on the basis of the information gathered from authentic sources. The constructed weighted average normal value of the un-branded sports shoes and branded sports shoes in the subject country comes to ***Rs./per pair and ***Rs./pair respectively. The weighted average normal value includes sports shoes of all categories and sizes. The methodology would take care of the issues raised by certain interested parties that appropriate comparability be made for category of shoes produced by domestic producers.

EXPORT PRICE

As regards the export price, the Authority notes that the import price of subject goods from the subject country (non-branded category) has been provided by the Customs Authorities and are also available from the DGCIS statistics. The import prices of the branded category of sports shoes have been made available by certain importers like M/s Reebok, M/s Adidas and M/s Bata. The ex-factory export price has been evaluated separately for non-branded and branded category of sports shoes as follows:-

The Directorate has on the basis of the information provided by the domestic industry, Customs Authorities and certain importers after co-relating the same with the DGCI&S data evaluated the ex-factory export price of non-branded category sports shoes by allowing adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, port expenses, inland freight etc. to an extent of *** *** *** *** *** Rs./pair on the basis of the best available information from the domestic industry and the importers and the consistent practice adopted in such cases.

As regards the branded category of shoes manufactured by M/s Moza Shoes (P) Limited and M/s Lakhani India Limited, the Authority has considered the information on imports as made available by M/s Bata and the Customs Authorities, since it is these range/category of sports shoes which compete with the branded sports shoes manufactured by the domestic producers. Adjustments as indicated in the foregoing para have also been allowed here. The weighted average ex-factory export price of the unbranded sports shoes and branded sports shoes comes to ** Rs./Pair and ** Rs./Pair respectively.

G. DUMPING - COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EX-FACTORY EXPORT PRICE

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the designated authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

For the purpose of fair comparison between the normal value and the export price, the Authority has considered taking into account the normal value and export price determined, as detailed above at ex-works level.

The dumping margin for exporters comes as under:

<u>Exporter/Producer</u>	<u>Normal value (Rs./pair)</u>	<u>Export price (Rs/pair)</u>	<u>Dumping margin (%)</u>
All exporters/ producers			
a) Unbranded category sports shoes	****	***	104.6
(b) Branded category sports shoes	****	***	92.6

The dumping margin for exporters for the two categories viz. unbranded and branded as indicated above comes 104.6 % and 92.6 % respectively.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

The Authority notes that various interested parties have made the following submissions:-

(i) Council for Leather Exports

- a) The branded category shoes should also include Nike, Reebok, Adidas and other brands also like Yonex, Converse, New Balance etc., which has also caused similar injury to the Indian industry by dumping of goods from PR China.
- b) The maximum value of landed imports in \$/pair have branded category of shoes should be raised to US\$25 as against the present level of US\$ 18.44 which does not cover major segment of footwear being imported under branded and are causing injury to the domestic industry.

(ii) M/s Moza Shoes (P) Limited

- a) The company has made losses due to very low utilization of capacity and that the growth was not possible due to imports of branded products. The imported goods are coming at low prices and, therefore, hardly any margin can be achieved. M/s Moza Shoes (P) Limited has been regularly exporting the branded products to USA, which is a proof of its expertise.
- b) There has been a serious injury to our production and marketing due to poor quality and on low price imports of sport shoes/casual shoes from China.
- c) The branded shoe market is the only growing market in India if the playing field is fair and the Chinese branded shoes are not allowed to be dumped in India, the domestic producers can grow and soon will be able to compete the exporters from outside as well as export in future.

(iii) **M/s Proline Sportsystem**

a) No injury has been caused to the domestic industry by imports as the domestic industry does not have technology nor are they manufacturing range of shoes being imported from China.

(iv) **M/s Bata India Ltd.**

(i) If restrictions are not imposed to prevent flooding of domestic industry, the entire footwear industry including the organized sector will stand to lose heavily.

(v) **M/s Reebok India Company**

(a) M/s Reebok caters to different segments, which do not hamper the growth of Indian, sports shoes industry at all. The biggest beneficiary of M/s Reebok launching its product in India have been the domestic industry who have benefited by the whole value chain moving up and the expansion of the footwear market in India.

(b) The definition of landed value as determined by the Designated Authority is incomplete and should include CVD and SAD into it.

(c) The shoes imported by M/s Reebok from China PR have not caused injury to the domestic industry as they are not similar the products made by the domestic producers in India.

(d) M/s Reebok is engaged in selling and marketing of performance shoes, which involves technologies like DMX, 3D, Hexalite and Blown Rubber, which are not available in India.

- (e) The prices at which M/s Reebok imports are far above the level at which the Indian industry operates. There are no Indian sports shoes, which are sold at such high price points as imported by M/s Reebok.
- (f) The data available on prices and quality shoes needs to be reviewed further by the Authority so as to arrive at information on the prevailing situation.
- (g) The total market size of sports footwear is 150 million pairs, which translates the imports into .05%, which is no injury to the domestic producers of sports footwear.

(vi)

M/s Adidas India Trading Trading Pvt. Ltd.

- a) Sufficient protection has been provided to the domestic industry, which goes against the norms level playing field and economies of scale.
- b) The petitioner has provided information in respect of the sports/casual goods of all types, and there is no segregation of information in this respect. This does not portray the correct picture.
- c) The petitioner has stated that the subject goods originating in China are being routed through Hong Kong, Nepal and Singapore and, therefore, the export from China is much higher. The submissions of the petitioner is not correct as while importing the goods the importer has to statutorily required to mention the country of origin and the port of export.

d) In response to the Disclosure Statement, it has been submitted that the imports of sports shoes by M/s Adidas have not caused any material injury to the domestic market.

e) In response to the Disclosure Statement, it has been submitted by M/s Adidas that the contention of the domestic industry that Chinese origin shoes are coming through other countries is wrong as the importer is required to declare the country of origin on the bill of entry. The profitability, market share and capacity utilization of the domestic manufactures has not gone down because of dumping of sports shoes of Chinese origin but because of other economic factors such as inefficiencies, low scale of operations, use of cheap raw materials, labour trouble etc. Domestic industry could set up world scale plant with modern technology and with the help of cheap labour export in a big way.

(vii) M/s Indian Sportswear Marketeers Association

a) As per the data provided by NCAER, the imports are a minuscule percentage of the total market.

b) The producers are sourcing footwear from the domestic manufacturers by utilizing their production capacities and this has led to increase in the capacity utilization of the domestic industry.

c) There has been steady increase in the average prices of the domestic sports shoes over the past two years and the increasing price trends have been witnessed even during the POI.

d) The exporters/producer and domestic manufacturers operate in a different market segment and that the imports have not caused any injury to the domestic producers.

The Authority in view of the submissions made by various interested parties, notes that Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, we may consider such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

The Authority observes the following

1. The imports of subject goods in absolute terms from PR China have increased from 4.68 lakh pair in 1999-2000 to 5.9 lakh pair in the POI (annualized), as per DGCIS's
2. The production of subject goods by the domestic industry has declined from 80.88 lakh pairs in 1999-2000 to 76.55 lakh pairs in POI annualized.
3. The capacity utilization in respect of subject goods of domestic industry has declined from 76.34% in 1999-2000 to 72.25 % in POI
4. The profitability of the industry has declined from Rs.*** in 1999-2000 to Rs.*** in POI.
5. The weighted average profit per pair has declined from Rs. *** per pair in 1999-2000 to Rs. *** per pair in POI. Also the net sales realization has been lower than the Non-Injurious Price (NIP) in the POI.
6. The sales realization of branded category sports shoes of M/s Lakhani India Limited has declined from Rs.** per pair in 1999-2000 to Rs.** per pair in the POI. The capacity utilization of M/s Moza Shoes (P) Limited and M/s Lakhani India Limited has remained sub optimal and there has been price suppression due to dumped imports of comparable category sports shoes during the POI. As regards the domestic industry's contention that there has been retardation in their growth regarding branded shoes category, the Authority notes that it has been mentioned in response to the Disclosure by the domestic industry that there has not been much demand of higher range of the branded category sports shoes. Thus, the Authority notes that the injury in the branded category sports shoes is best restricted to the category of shoes being manufactured and sold by M/s Moza Shoes (P) Limited and M/s Lakhani India Limited in the POI and that feeble demand of higher end sports shoes have been a restricting factor to the growth of higher end category of shoes.

The above economic indicators collectively and cumulatively indicate that the domestic industry has suffered material injury due to the dumped imports. In establishing that the material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country, the Authority holds that the dumped imports of subject goods from the subject country have depressed the prices of the subject goods in the domestic market and, therefore, forced the domestic industry to sell at un-remunerative prices resulting in decline in profitability and financial losses to the domestic industry. Since the overall demand of the subject goods cumulatively has not declined, it has not been a contributing factor to the injury caused to the domestic industry.

I. CONCLUSION ON INJURY:

The Authority concludes that

- a) The subject goods in all forms viz. category, size, branded/non-branded originating in or exported from the subject country have been exported to India below its normal value.
- b) The domestic industry has suffered material injury by way of financial losses due to depressed Net Sales Realisation on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods.
- c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.
- d) Various economic indicators relating to domestic industry such as production, average sales realisation and financial losses collectively and cumulatively established at the domestic industry has suffered material injury.

It is, therefore, seen that the domestic industry has suffered material injury from the dumped imports. In establishing that the material injury to the domestic industry has been caused by the imports from the subject country, the Authority holds that dumped exports from the subject country have depressed the prices of subject goods in the domestic market and forced the domestic industry to sell at un-remunerative prices, resulting in financial losses to the domestic industry. The domestic industry has suffered injury on account of loss in production, fall in capacity utilisation and decline in net sales realization below NIP.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

Certain interested parties have submitted that the anti-dumping duties are protectionist in nature. The Authority notes that it has been indicated by M/s Reebok that they have helped in transfer of technology and R&D activities to develop the branded sports shoes market in India. The Authority also notes that along with this technology transfer certain domestic producers like M/s Moza Shoes (P) Limited and M/s Lakhani India Limited have set up the production facilities to cater to the demand of such category branded shoes to M/s Reebok, M/s Adidas and M/s NIKE etc. If the phenomena of dumping affects the performance and health of the domestic producers, it would ultimately affect the availability of the subject goods to the consumers also. It is also true that the imposition of anti-dumping duties may affect the price level of the subject goods to a certain extent to the end consumer. However, by virtue of levy of such anti-dumping duties, the unfair advantages gained by the dumping practices would be limited and this would further prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

K. LANDED VALUE

The landed value has been determined after adding applicable level of custom duties (except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A) and one percent towards landing charges.

L. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing, that:

- a. The subject goods in the forms and category as indicated in the foregoing Para C(1) originating in or exported from the subject country have been exported to India below its normal value.
- b. The domestic industry has suffered material injury by way of loss in production and financial losses due to depressed Selling prices on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods.
- c. The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country. The authority recommends anti-dumping duty on imports of subject goods falling under Chapter 64 originating in or exported from the subject country.

d. It was considered to recommend amount of Anti-Dumping duty equal to margin of dumping or less so as to remove injury to the domestic industry. Accordingly, it is proposed that definitive anti-dumping duties be imposed, on all imports of Sports Shoes originating in or exported from the subject country i.e. Peoples Republic of China falling under chapter 64 (Custom head 6402 to 6405) of the Customs Tariff. The subject goods are PVC injected shoes, canvas shoes with rubber soles and Sports shoes with rubber synthetic or textiles or combination materials and with rubber or EVA sole only as also indicated in foregoing para C(1). The anti-dumping duty shall be the difference between the amounts mentioned in column 3 below and the landed value of imports in US\$/pair.

1	2	3
Sl.No	Name of the exporter/producer	Amount (US\$/pair)
	All exporters/ producers from PR China	
	(a)Unbranded category sports shoes only excluding branded category sports shoes	5.044
	(b)Branded category sports shoes (viz. Reebok, Nike, Adidas, Converse, Fila, New Balance, K swiss, Sketchers, Proline, Bata, X-ess, Diana Pi, X-iang, Harling, Lagos etc.)	12.9

Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Subject to above, the Authority confirms the preliminary finding dated 25.1.2001.

An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority & Addl. Secy.

